



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 11, 2019/ आषाढ़ 20, 1941
No. 243] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 11, 2019/ASHADHA 20, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण अधिसूचना

मुंबई, 21 जून, 2019

संख्या टीएएमपी/46/2016-बीपीसीएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में प्रचालन कर रहे भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के वर्तमान दरमानों की वैधता का, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, विस्तार करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/46/2016-बीपीसीएल

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

आवेदक

गणपूर्ति

- (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जून, 2019 के 14 वें दिन पारित)

मामला जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) स्थित भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा प्रचालित की जा रही तरल कार्गो बर्थ के वर्तमान दरमानों के विस्तार से संबंधित है।

2.1 बीपीसीएल के वर्तमान दरमानों का इस प्राधिकरण द्वारा 8 फरवरी, 2017 के आदेश संख्या टीएएमपी/46/2016-बीपीसीएल के द्वारा प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के अंतर्गत अनुमोदित किये गए थे। वह आदेश 6 मार्च, 2017 के राजपत्र में राजपत्र संख्या 94 में अधिसूचित हुआ था। निर्धारित प्रशुल्क वैधता 31 मार्च 2019 तक थी।

2.2. इसके अतिरिक्त, बीपीसीएल के अनुरोध के आधार पर इस प्राधिकरण ने 25 फरवरी 2019 के आदेश संख्या टीएएमपी/46/2016-बीपीसीएल के द्वारा मौजूदा दरमानों की वैधता का 3 महीने के लिए, यानी 01 अप्रैल, 2019 से 30 जून, 2019 तक, विस्तार किया गया था।

3.1. इस पृष्ठभूमि में, बीपीसीएल ने 12 जून, 2019 के अपने पत्र संख्या बीपीसीएल/जेएनपी/ओपीएस के द्वारा अपने मौजूदा दरमानों में 4 महीने की अवधि अर्थात् 30 अक्टूबर, 2019 तक, के लिए विस्तार करने का अनुरोध किया है। बीपीसीएल ने यह भी बताया है कि वह नए प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के अनुसार प्राधिकरण की अपेक्षाओं के अनुरूप नया प्रस्ताव 30 अक्टूबर, 2019 या उससे पहले दायर कर देगा।

4.1. चूंकि बीपीसीएल के मौजूदा प्रशुल्क की वैधता 30 जून, 2019 को समाप्त हो जायेगी और बीपीसीएल द्वारा ऊपर बताए गए कारणों से किये गए अनुरोध तथा प्रशुल्क में निर्वात से बचने के लिए बीपीसीएल के मौजूदा दरमानों को 30 जून, 2019 से आगे विस्तार किया जाना उपयुक्त समझा जाता है।

4.2. जैसा पिछली बार किया गया था यह प्राधिकरण बीपीसीएल के वर्तमान प्रशुल्क की अवधि में 3 महीने का अर्थात् 01 जुलाई 2019 से 30 सितंबर 2019 तक विस्तार करने को प्रवृत्त है न कि बीपीसीएल द्वारा किये गए अनुरोध के अनुसार 30 अक्टूबर, 2019 तक।

4.3. यहां तक प्रस्ताव दायर करने का संबंध है, यह बात ध्यान में रखते हुए कि वैधता विस्तार का 30 सितंबर, 2019 तक किया गया है बीपीसीएल को सलाह दी जाती है कि वह सामान्य संशोधन का अपना प्रस्ताव 31 अगस्त, 2019 तक दायर करे न कि 30 अक्टूबर, 2019 तक या उससे पहले।

4.4. यदि निष्पादन की समीक्षा के दौरान 01 अप्रैल, 2019 के बाद की अवधि के लिए ग्राह्य लागत और अनुज्ञेय प्रतिफल के अतिरिक्त कोई अधिशेष पाया जाता है तो ऐसे अतिरिक्त अधिशेष को सरकार द्वारा जारी और इस प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित महापत्तन न्यासों में बीओटी प्रचालकों के प्रशुल्क निर्धारण दिशानिर्देश 2019 के खंड 3.1.2 के अनुसार निपटाया जायेगा जो पहले पूर्व में प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 द्वारा शासित होते थे।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, वित्त (सदस्य)

[विज्ञापन-III/4असा./121/19]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 21st June, 2019

No. TAMP/46/2016-BPCL.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Bharat Petroleum Corporation Limited operating in the Jawaharlal Nehru Port Trust as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/46/2016-BPCL

The Bharat Petroleum Corporation Limited

Applicant

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 14 day of June 2019)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) operating the Liquid Cargo berth at the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT).

2.1 The existing Scale of Rates (SOR) of BPCL was approved by this Authority vide Order No. TAMP/46/2016-BPCL dated 8 February 2017 under the Tariff Guidelines of 2005. This Order was notified in the Gazette of India on 06 March 2017 vide Gazette No. 94. The Order prescribed a tariff validity till 31 March 2019.

2.2 Further, based on the request of BPCL, this Authority vide its Order No. TAMP/46/2016- BPCL dated 25 February 2019 has extended the validity of the existing tariff of BPCL for a period of 3 months i.e. from 01 April 2019 to 30 June 2019.

3.1 In this backdrop, the BPCL vide its letter dated no. BPCL/JNP/OPS dated 12 June 2019 had requested this Authority to grant an extension of the existing Scale of Rates for a further period of 4 month i.e. upto 30 October 2019. The BPCL has also stated that, the new proposal would be submitted by or before 30 October 2019 on completion as per TAMP requirements as per the new Tariff Guidelines, 2019.

4.1 Since the validity of the existing tariff of BPCL will expire on 30 June 2019 and based on the request made by BPCL for the reasons cited by it and in order to avoid a vacuum in the tariff, it is felt appropriate to extend the validity of the existing tariff of BPCL beyond 30 June 2019.

4.2 As done in the last occasion, this Authority is inclined to extend the validity of the existing tariff of BPCL for a period of 3 months i.e. from 01 July 2019 to 30 September 2019, instead of 30 October 2019, as requested by BPCL.

4.3 With regard to submission of the proposal, considering that the validity has been extended upto 30 September 2019, the BPCL is advised to file its proposal for general revision of its tariff by 31 August 2019, instead of on or before 30 October 2019.

4.4 If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 01 April 2019, during the review of its performance, such additional surplus will be dealt with as per Clause 3.1.2. of the Tariff Guidelines, 2019 for determination of tariff for BOT operators operating in Major Port Trusts and previously governed by 2005 Tariff Guidelines issued by the Government and notified by this Authority in the Gazette of India.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./121/19]